बुधवार
25 नवम्बर 2026
● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 304
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

34 साल से देहरादून का विश्वास

दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94 email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

पहाड़ में एक पूरा गांव 'उजड़ा'

प्रदेश के उत्तरकाशी जिले के पवाणी गांव में आग से 30 घर जले

कार्यालय संवाददाता

देहरादून/उत्तरकाशी। पहाड़ में आग लगती है तो सिर्फ लकड़ी के मकान नहीं जलते, उनके साथ पीढ़ियों की स्मृतियां, परिवारों की जमा पूंजी और जीवनभर की मेहनत भी राख हो जाती है। उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड के पवाणी गांव में आग ने कुछ ऐसा ही मंजर छोड़ दिया। देखते ही देखते 33 मकान आग की भेंट चढ़ गए। जिन घरों में कुछ समय पहले तक चूल्हे जल रहे थे, परिवारों की रौनक थी और जीवन की तमाम जरूरतें सहेजकर रखी गई थीं, वहां अब राख और मलबे के सिवाय कुछ नहीं बचा। इस अग्निकांड को केवल एक गांव में आग लगने की घटना मानकर आगे बढ़ जाना आसान है, लेकिन इसके पीछे पहाड़ की एक बड़ी और पुरानी समस्या छिपी है। सवाल यह है कि आखिर पहाड़ के गांव आग के सामने इतने असहाय क्यों हैं? एक मकान में लगी आग देखते ही देखते 33 मकानों तक कैसे पहुंच गई? क्या गांवों में अग्निशमन की कोई प्रभावी व्यवस्था है? और क्या हर बड़े हादसे के बाद मुआवजे और मदद की घोषणाओं के भरोसे ही ग्रामीणों को छोड़ दिया जाएगा?



◆लोगों की वर्षों की मेहनत, जमा पूंजी और पुश्तैनी विरासत खाक
◆पहाड़ में अग्निकांड से निपटने की व्यवस्था पर फिर उठे सवाल

पवाणी गांव में लकड़ी के मकानों की अधिकता और गैस सिलिंडर फटने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों ने एक के बाद एक मकानों को अपनी चपेट में लिया। ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी जान बचाने और आग को दूसरे घरों तक फैलने से रोकने की थी। लेकिन जब आग विकराल रूप ले लेती है तो सीमित संसाधनों के सहारे उसे रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है।

इस हादसे ने पहाड़ के पारंपरिक गांवों की संवेदनशीलता भी उजागर कर दी है। लकड़ी के मकान पहाड़ी वास्तुकला, स्थानीय जलवायु और जीवनशैली का हिस्सा रहे हैं। लेकिन जब मकान एक-दूसरे के बेहद करीब हों, छतें और निर्माण सामग्री ज्वलनशील हों तथा पानी और अग्निशमन के संसाधन दूर हों तो एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे गांव के लिए तबाही बन सकती है।

सबसे बड़ा संकट उन परिवारों का है, जिन्होंने इस आग में अपना सब कुछ खो दिया। मकान दोबारा बन सकता है, लेकिन उसमें संजोई गई यादें, दस्तावेज, अनाज, कपड़े, घरेलू सामान और पुश्तैनी धरोहर वापस नहीं लाई जा सकती। ऐसे परिवारों के सामने अब सिर छिपाने से लेकर रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने तक का संकट खड़ा होगा। पवाणी का अग्निकांड व्यवस्था के लिए भी एक चेतावनी है। उत्तरकाशी जैसे पर्वतीय जिले में दूरस्थ गांवों तक आपातकालीन सेवाएं पहुंचाना पहले से ही चुनौतीपूर्ण है। सड़क, दूरी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राहत पहुंचने में लगने वाला समय कई बार नुकसान को कई गुना बढ़ा देता है। ऐसे में सवाल केवल अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता का नहीं, बल्कि गांव स्तर पर आग से बचाव की पूरी व्यवस्था विकसित करने का है।

सरकार और प्रशासन के सामने अब तत्काल राहत के साथ पुनर्वास की चुनौती है। प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा, अस्थायी आवास, भोजन, कपड़े और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि क्षतिग्रस्त परिवारों को मकान दोबारा बनाने के लिए

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

मुख्यमंत्री ने 36 नवनियुक्त नायब तहसीलदारों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में 36 नवनियुक्त नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।

आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में 36 नवनियुक्त नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने 36 चयनित अभ्यर्थियों में 13 बेटियों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सफलता सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रही प्रदेश की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त अधिकारियों की इस उपलब्धि के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन



और दृढ़ संकल्प के साथ ही उनके माता-पिता एवं गुरुजनों का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र के साथ ही आप सभी को जनसेवा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिली है। आपके कार्यों से आमजन को समय पर राहत मिले, यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नायब तहसीलदार राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके कार्यों का सीधा संबंध आमजन की भूमि, आजीविका और अधिकारों से है। उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से नामांतरण, पैमाइश, सीमांकन एवं राजस्व अभिलेखों से जुड़े मामलों का पूरी सावधानी, संवेदनशीलता और समयबद्धता के साथ निस्तारण करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि एक किसान के लिए उसकी भूमि परिवार की आजीविका और बच्चों के भविष्य का आधार होती है। अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण के निस्तारण में इससे जुड़े परिवारों की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनें तथा आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से तहसीलों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में दूरस्थ गांवों से आने वाले लोगों, विशेषकर बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। सभी अधिकारी अपने सेवाकाल में किसी भी प्रकार के दबाव, सिफारिश अथवा प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना नियमों, कानून और तथ्यों के आधार पर निर्णय लें। उन्होंने कहा कि बिना किसी सिफारिश के आने वाले व्यक्ति के जायज कार्य का भी पूरी तत्परता से निस्तारण करना निष्पक्ष प्रशासन की पहचान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का मूल मंत्र 'सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण' है। सभी अधिकारी इस मंत्र को अपनी कार्यशैली में शामिल करें। कार्यप्रणाली को सरल

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

दून वैली मेल

संपादकीय

देश में मौसम के दो चेहरे

भारत इन दिनों मौसम के दो बिल्कुल अलग-अलग रंग देख रहा है। उत्तर भारत के कश्मीर में बर्फबारी से वादियां सफेद हो रही हैं तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में बारिश का दौर जारी है। कहीं बर्फ की चादर बिछ रही है तो कहीं आसमान से पानी बरस रहा है। देश के एक हिस्से में सर्दी दस्तक दे रही है, जबकि दूसरे हिस्से में बारिश जनजीवन को प्रभावित कर रही है। मौसम के इस विरोधाभास के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रकृति का मिजाज तेजी से बदल रहा है और क्या हमारी व्यवस्थाएं इन बदलावों से निपटने के लिए तैयार हैं? भारत की भौगोलिक परिस्थितियां उसे मौसम के लिहाज से विशिष्ट बनाती हैं। हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बर्फबारी और बारिश होती है, जबकि दक्षिण भारत में उत्तर-पूर्वी मानसून वर्षा का प्रमुख कारण बनता है। ऐसे में एक ही समय में देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग मौसमी परिस्थितियों का होना असामान्य नहीं है। लेकिन चिंता का विषय मौसम की विविधता नहीं, बल्कि उसकी बढ़ती अनिश्चितता है। पिछले कुछ वर्षों में मौसम के व्यवहार में जिस तरह के बदलाव दिखाई दिए हैं, उन्होंने कृषि से लेकर शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन तक सभी क्षेत्रों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। कहीं कम समय में अत्यधिक बारिश हो रही है तो कहीं लंबे समय तक सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। कहीं सर्दियों में अपेक्षित बर्फबारी नहीं हो रही तो कहीं अचानक तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका असर सीध जनजीवन और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। विशेष रूप से हिमालयी राज्यों के लिए मौसम का बदलता मिजाज चिंता का विषय है। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक बर्फबारी केवल पर्यटन से जुड़ा विषय नहीं है। हिमालय की बर्फ देश की नदियों और जलस्रोतों के लिए महत्वपूर्ण है। समय पर हिमपात होने से जलचक्र को मजबूती मिलती है, लेकिन असामान्य मौसम, अत्यधिक हिमपात और अचानक बारिश आपदा का कारण भी बन सकती है। उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में इसका महत्व और बढ़ जाता है। यहां पहले ही अनियोजित निर्माण, कमजोर ढलानों, सड़क कटान और पारिस्थितिक असंतुलन ने जोखिम बढ़ा दिया है। दूसरी ओर तमिलनाडु और केरल में बारिश का दौर शहरी व्यवस्थाओं की परीक्षा लेता है। जल निकासी की कमजोर व्यवस्था, नदियों और नालों पर अतिक्रमण तथा अनियोजित शहरीकरण बारिश को राहत के बजाय आफत में बदल देते हैं। हर साल बारिश के दौरान जलभराव, यातायात बाधित होने और जनजीवन प्रभावित होने की घटनाएं सामने आती हैं। इसके बावजूद शहरों की बुनियादी व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार नहीं दिखाई देता। दरअसल, मौसम का बदलता स्वरूप अब केवल मौसम विभाग के पूर्वानुमान तक सीमित रहने वाला विषय नहीं है। यह कृषि, खाद्य सुरक्षा, पेयजल, ऊर्जा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। हालांकि किसी एक बर्फबारी या बारिश की घटना को जलवायु परिवर्तन का सीधा परिणाम नहीं माना जा सकता, लेकिन लगातार बदलते मौसमी पैटर्न का वैज्ञानिक अध्ययन और उसके अनुरूप नीतियां बनाना जरूरी है। विडंबना यह है कि सरकारों का ध्यान अब भी आपदा के बाद राहत और पुनर्वास पर अधिक रहता है। आपदा से पहले तैयारी, जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान, मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणाली और स्थानीय स्तर पर बचाव की व्यवस्था को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिलती। पहाड़ों में विकास के नाम पर प्रकृति की अनदेखी और मैदानी शहरों में बेतरतीब निर्माण इस समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। अब समय आ गया है कि मौसम को महज मौसमी घटना मानने के बजाय विकास की नीतियों का महत्वपूर्ण आधार बनाया जाए। हिमालयी क्षेत्रों में निर्माण की वैज्ञानिक सीमाएं तय हों, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित न किया जाए और वर्षा जल निकासी की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। मौसम संबंधी चेतावनियों को समय रहते प्रशासनिक कार्रवाई में बदलना भी जरूरी है। कश्मीर की बर्फ और दक्षिण भारत की बारिश भले ही दो अलग-अलग मौसमी तस्वीरें हों, लेकिन दोनों देश को एक ही संदेश दे रही हैं। प्रकृति के संकेतों को समझने और उनके अनुरूप अपनी व्यवस्थाएं बदलने का समय आ गया है। विकास की दौड़ में यदि प्रकृति के संतुलन को ही भुला दिया गया तो मौसम का यह बदलता मिजाज भविष्य में और बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकता है। सवाल यह नहीं कि आज देश में कहां बर्फ गिर रही है और कहां बारिश हो रही है, सवाल यह है कि कल आने वाली मौसमी चुनौतियों से निपटने के लिए देश कितना तैयार है?

नौकरी लगाने के नाम पर ठगे 31 लाख रुपये

संवाददाता

देहरादून। नौकरी लगाने के नाम पर 31 लाख रूपये की ठगी के मामले में पुलिस ने पति पत्नी सहित तीन पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।प्राप्त जानकारी के अनुसार हरिद्वार रोड ऋषिकेश निवासी राजे सिंह ने नेहरू कालोनी थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पहचान अलकनंदा एन्क्लेव निवासी नरेन्द्र प्रकार उसकी पत्नी रविकांता शर्मा व व विजय भटट से हुई। तीनों ने उसको नौकरी लगाने का झांसा दिया और समय-समय पर उससे रूपयों की मांग करते रहे और उससे 31 लाख 27 हजार रूपये ले लिया। लेकिन जब उसने नौकरी की बात करी तो वह उसको टालते रहे। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब उसकी नौकरी नहीं लगी तो उसने अपने रूपये वापस मांगे तो उक्त लोगों ने उसके साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी।

थाली में 'बीमारी' परोस रहा 'बाजार'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। इंसान जिंदा रहने के लिए खाना खाता है, लेकिन अब सवाल यह है कि कहीं खाना ही इंसान को बीमार तो नहीं बना रहा? जिस दूध को बच्चों की सेहत का आधार माना जाता है, उसकी शुद्धता पर सवाल हैं। जिस सब्जी को पौष्टिक समझकर थाली में सजाया जाता है, उसमें कीटनाशकों के अवशेष होने का खतरा है। जिन मसालों से भोजन का स्वाद बढ़ता है, उनमें मिलावट की शिकायतें सामने आती रहती हैं। पैकेट में बंद खाद्य पदार्थों की चमक और आकर्षक विज्ञापनों के पीछे पोषण का कितना सच छिपा है, यह भी किसी से छिपा नहीं। आखिर हमारी थाली में क्या है? पोषण, रसायन, मिलावट या धीमे-धीमे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व? यह सवाल अब सिर्फ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का नहीं, बल्कि जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा का बन चुका है। बाजार में बिकने वाली हर चीज पर भरोसा करना उपभोक्ता की मजबूरी है, लेकिन उस भरोसे की कीमत उसे अपनी सेहत से चुकानी पड़े तो जिम्मेदार कौन होगा? मुनाफे के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले, गुणवत्ता की अनदेखी करने वाले कारोबारी या आंखें मूंदकर बैठा निगरानी तंत्र?

खाद्य कारोबार में मुनाफा कमाना गलत नहीं है, लेकिन जब मुनाफे की भूख इंसान की सेहत से बड़ी हो जाए तो यह कारोबार नहीं, अपराध की श्रेणी में आता है। दूध में मिलावट, नकली घी, घटिया खाद्य तेल, मसालों में मिलावट और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की शिकायतें बार-बार सामने आती हैं। सवाल यह है कि आखिर लोगों की थाली में जहर पहुंचाने वालों के मन में कानून का डर क्यों नहीं है? सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि आम आदमी अपनी आंखों से खाद्य पदार्थों की शुद्धता नहीं पहचान सकता। दूध देखकर उसकी गुणवत्ता का पता नहीं चलता। फल की चमक उसके सुरक्षित होने का प्रमाण नहीं है। सब्जियों का ताजा दिखना इस बात की गारंटी नहीं कि उनमें हानिकारक अवशेष नहीं हैं। उपभोक्ता दुकान से सामान खरीदता है, बिल चुकाता है और भरोसे के साथ परिवार को खिलाता है। लेकिन अगर वही सामान स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाए तो उसकी सुनवाई कहां होगी?

◆खेत में रसायन, बाजार में मिलावट और थाली में खतरा
◆देश में मुनाफे की भूख, इंसान की सेहत पर पड़ रही भारी
◆मिलावट का जाल, मुनाफे की भूख में सेहत से खिलवाड़
◆जिस अन्न को अमृत माना, उसकी शुद्धता पर भरोसा नहीं

समस्या की जड़ केवल दुकानों तक सीमित नहीं है। खेतों में अत्यधिक और अनुचित रासायनिक इस्तेमाल, कीटनाशकों के अवशेष, दूषित पानी, खाद्य पदार्थों का असुरक्षित भंडारण और प्रसंस्करण से लेकर पैकेजिंग तक कई स्तरों पर गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ हमारी भोजन संस्कृति भी तेजी से बदल रही है। घर के ताजे भोजन की जगह पैकेटबंद खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, अधिक नमक, चीनी और वसा वाले उत्पाद लेते जा रहे हैं। बाजार स्वाद बेच रहा है, विज्ञापन सेहत का सपना दिखा रहे हैं और उपभोक्ता इस चमक-दमक के बीच यह भूलता जा रहा है कि भोजन का पहला उद्देश्य शरीर को पोषण देना है। सुविधा और स्वाद की इस दौड़ में सेहत पीछे छूट रही है।

मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी बीमारियों का बढ़ता बोझ एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। इनके पीछे कई कारण हैं, लेकिन अस्वस्थ खानपान भी एक महत्वपूर्ण कारण है। दूषित

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

अब सवाल पूछना ही होगा

क्या सुरक्षित भोजन अब केवल अमीरों का विशेषाधिकार बन जाएगा? क्या आम आदमी को अपने बच्चों के लिए दूध खरीदते समय भी मिलावट का डर पालना पड़ेगा? क्या हर फल, सब्जी और मसाले की शुद्धता जांचने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की ही है? सरकारें स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने की बात करती हैं, लेकिन बीमारियों की एक बड़ी वजह बनने वाले असुरक्षित खानपान पर रोक लगाने के लिए कितनी गंभीर हैं? भोजन कोई विलासिता नहीं, जीवन की बुनियादी जरूरत है। इसे मुनाफाखोरों के हवाले नहीं किया जा सकता। खाद्य सुरक्षा विभागों को नियमित और पारदर्शी जांच करनी होगी। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होगी। मिलावट के दोषियों पर कठोर कार्रवाई करनी होगी और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को जवाबदेह बनाना होगा।

चुनाव की 'आहट' सड़कों पर 'जनसैलाब'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू होने के साथ ही सड़कों का सियासी तापमान भी बढ़ने लगा है। सरकार के खिलाफ धरने-प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। कहीं बेरोजगार युवा नौकरी की मांग लेकर सड़कों पर हैं तो कहीं कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कहीं जमीन का सवाल है तो कहीं भर्ती, भ्रष्टाचार, महंगाई और जनसुविधाओं को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। सत्ता के गलियारों से लेकर सड़कों तक हलचल बढ़ने लगी है। साफ है कि चुनाव करीब आते ही जनता के मुद्दे एक बार फिर राजनीतिक संघर्ष का हथियार बनने लगे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में आंदोलनों का अपना इतिहास रहा है। अलग राज्य का गठन ही लंबे जनसंघर्ष का परिणाम था। इसलिए यहां धरना-प्रदर्शन महज विरोध का माध्यम नहीं, बल्कि राजनीतिक चेतना और जनभावनाओं की अभिव्यक्ति भी रहे हैं। लेकिन मौजूदा दौर में आंदोलनों के बढ़ते दायरे के साथ उनके राजनीतिक इस्तेमाल का सवाल भी खड़ा होने लगा है।

भाजपा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चुनावी मैदान में उतरने से पहले वह जनता के बीच अपने कामकाज का हिसाब कैसे रखेगी। रोजगार, भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता, महंगाई, भ्रष्टाचार, पलायन और पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं की कमी ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। बेरोजगार युवाओं का असंतोष सरकार के लिए खास तौर पर चुनौती बन सकता है। नकलरोधी कानून और भर्ती प्रक्रिया में सुधार के दावों के बावजूद युवाओं की अपेक्षाएं पूरी तरह शांत नहीं हुई हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी सड़कों पर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है। भूमि बचाओ, धामी हटाओ जैसे अभियानों से लेकर विभिन्न जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति इसी राजनीतिक तैयारी का हिस्सा है। कांग्रेस के लिए चुनौती केवल सरकार की नाकामियां गिनाना नहीं, बल्कि आंदोलनों को व्यापक जनसमर्थन में बदलना भी है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से मिल रहे फीडबैक के आधार पर संगठन अपनी आगामी रणनीति तैयार कर रहा है।

इस राजनीतिक परिदृश्य में क्षेत्रीय दलों और दूसरे राजनीतिक संगठनों की सक्रियता भी बढ़ रही है। उत्तराखंड क्रांति दल राज्य के सवालों को लेकर अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है। आम आदमी पार्टी समेत अन्य दल भी सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। ऐसे में छोटे-बड़े आंदोलन राजनीतिक दलों के लिए जनता के बीच पहुंचने का माध्यम बन रहे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल उन मुद्दों को भी उठाने लगते हैं, जिन्हें सामान्य दिनों में अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिलती। वर्षों से लंबित समस्याएं अचानक राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ जाती हैं। ज्ञापन दिए जाते हैं, धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं और सरकार से जवाब मांगा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों का समाधान भी होगा या फिर चुनाव के बाद आंदोलनकारी एक बार फिर उसी व्यवस्था के सामने खड़े होंगे?

सरकार के लिए भी यह समय केवल विपक्ष के आरोपों का जवाब देने का नहीं, बल्कि असंतोष के वास्तविक कारणों को समझने का है। हर प्रदर्शन को राजनीतिक साजिश बताकर खारिज नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है और सरकार की जवाबदेही भी। यदि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, युवा रोजगार के लिए आवाज उठा रहे हैं और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

◆धरने और प्रदर्शनों से गरमाने लगी सियासत
◆सत्ता को घेरने के लिए आंदोलनों का सहारा
◆कार्मिकों और बेरोजगारों तक ने खोला मोर्चा

आठ किलो गांजे के साथ दो गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने आठ किलो गांजे के साथ दो लोगों को गिरफतार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रायवाला थाना पुलिस ने पेट्रोल पम्प के पास एक स्कूटी पर सवार दो लोगों को रूकने का इशारा किया। पुलिस को देख वह स्कूटी को तेजी से भगा ले गये। पुलिस ने पीछा कर उनको थोडी दूरी पर ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उनके कब्जे से आठ किलो 688 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम प्रवीण पुत्र प्यारे लाल व अजय कुमार पुत्र योगेन्द्र प्रसाद दोनों निवासी वनखण्डी बताया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

मकान का ताला तोड जेवरात व नगदी चोरी

संवाददाता

देहरादून। चोरों ने मकान का ताला तोड वहां से लाखों के जेवरात व नगदी चोरी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार डांडी रानीपोखनी निवासी अशोक कुमार ने रानीपोखरी थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह परिवार के साथ बाहर गया था। आज जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसके मकान का ताला टूटा हुआ था तथा अन्दर सारा सामान बिखरा हुआ था। चोर उसके यहां से लाखो रूपये के जेवरात व नगदी चोरी करके ले गये हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

शराब के साथ दो गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने श्यामपुर के पास एक युवक को संदिग्ध अवस्था में घुमते हुए देखा तो उसको रूकने का इशारा किया। पुलिस को देख वह भाग खडा हुआ। पुलिस ने पीछा कर उसको थोडी दूरी पर ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके कब्जे से 45 पव्वे शराब के बरामद कर लिये। पूछताछ में उसने अपना नाम विजय पुत्र गोकुल लाल निवासी भल्ला फार्म श्यामपुर बताया। इसके साथ ही डालनवाला कोतवाली पुलिस ने रिस्पना नगर से एक युवक को 5० पव्वे शराब के साथ गिरफ्तार किया। जिसने अपना नाम राहुल पुत्र ओमपाल निवासी डीएल रोड बताया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

चरस के साथ दो गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने चरस के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासनगर कोतवाली पुलिस ने एक आल्टो कार को रूकने का इशारा किया। पुलिस को देख कार चालक कार को तेजी से भगा ले गया। पुलिस ने पीछा कर उनको थोडी दूरी पर ही रोक लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उनके कब्जे से 419.3 ग्राम चरस बरामद कर ली। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम बृजलाल पुत्र शिवलाल व दिनेश पुत्र मेहक दोनों निवासी शिमला बताया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

स्मैक के साथ गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सहसपुर थाना पुलिस ने लांघा रोड पर एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में घुमते हुए देखा तो उसको रूकने का इशारा किया। पुलिस को देख वह भाग खडा हुआ। पुलिस ने पीछा कर उसको थोडी दूरी पर ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके कब्जे से 7. ०2 ग्राम स्मैक बरामद कर ली। पूछताछ में उसने अपना नाम सद्दाम पुत्र इकराम निवासी कुशालपुर सहसपुर बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

भाजपा के 65 पार के जवाब में कांग्रेस का 45 पार का दांव

हल्द्वानी(आरएनएस)। भाजपा के 65 पार के चुनावी लक्ष्य के जवाब में कांग्रेस ने उत्तराखंड में 45 पार का नारा बुलंद कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोमवार को फॉर्चुन होटल में पत्रकार वार्ता में दावा किया था कि प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने अपनी दावेदारी से किनारा करते हुए कहा कि कांग्रेस में उनसे भी खूबसूरत और कई सक्षम चेहरे हैं। मुख्यमंत्री का फैसला राहुल गांधी और पार्टी हाईकमान करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के 65 पार के नारे के सवाल पर रावत ने कहा कि कांग्रेस 45 पार करेगी और पूर्णबहुमत से सरकार बनाएगा। बकौल रावत 'मैं चाहता स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का सशक्त होना भी बहुत जरूरी है।'

कांग्रेस किसी एक व्यक्ति के बजाय पार्टी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चुनाव में सेनापति की भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री का निर्णय चुनाव जीतने के बाद विधायक दल और हाईकमान करेंगे। नए चेहरों को मौका देने की जरूरत बताते हुए उन्होंने संन्यास के सवाल पर चुटकी ली कि वह ऐसे संन्यासी हैं, जो चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं और न थकते हैं। चुनाव कहां से लड़ेंगे, इस पर बोले कि अब उनके दिल की डोर किसी और के हाथ में हैइससे पूर्व हरीश रावत ने कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की पुस्तक 'बिलांगिंग ः ए जर्नी ऑफ लव' पर चर्चा करते हुए जमकर तारीफ की। साथ ही इसकी प्रतियां सभी पत्रकारों को भेंट की। इस मौके पर विधायक सुमित हृदयेश, जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल, महानगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट, ललित जोशी, खजान पांडे, भोला भट्ट, केदार पलड़िया, प्रयाग भट्ट, हरीश रावत आदि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री धामी के पांच साल के कामकाज पर नंबर देने के सवाल पर रावत ने कहा कि कॉपी में कुछ लिखा हो, तभी तो नंबर दूं। उन्होंने महिला अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ मुद्दावार अभियान चलाने की घोषणा की। कहा कि न्याय यात्रा को जनता का अच्छा समर्थन मिला है। अब कार्यकर्ता बैठक अभियान के तहत जनता के बीच जाकर स्थानीय समस्याएं सुनेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जल्द उत्तराखंड का दौरा करेंगे।

धारचूला विधायक हरीश धामी का गनर बदले जाने और उनकी सुरक्षा को लेकर रावत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे विधायक के सम्मान और जनता के प्रतिनिधित्व से जुड़ा गंभीर मामला बताया। कहा कि कभी-कभी जनप्रतिनिधियों की नाराजगी सामने आती है, ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज करने के बजाय संवाद से समाधान निकालना चाहिए। कांग्रेस पूरी मजबूती से हरीश धामी के साथ खड़ी है।

दो सूत्रीय मांगों को लेकर धरने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

रुद्रपुर(आरएनएस)। दो सूत्रीय मांगों को लेकर विकास भवन के बाहर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सेविका और मिनी कार्यकर्ताओं का धरना-प्रदर्शन मंगलवार को 15वें दिन भी जारी रहा।

सुबह से ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विकास भवन पहुंच गईं और नारेबाजी कर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक सरकार लिखित में शासनादेश जारी नहीं करती, तब तक वे धरने से नहीं उठेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रुचिका अरोरा ने बताया कि प्रदर्शन कर रही कार्यकर्ताओं की दो प्रमुख मांगें हैं। पहला राज्य सरकार अपने स्तर से उनके मानदेय में 14० रुपये प्रतिदिन की वृद्धि करे और केंद्र सरकार को 15० रुपये प्रतिदिन की अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव भेजे। दूसरा सेवानिवृत्ति पर बिना किसी अतिरिक्त अर्हता की शर्त के 1० लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का शासनादेश जारी किया जाए।

कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक 1० लाख रुपये की आर्थिक सहायता का शासनादेश जारी नहीं होता, तब तक उनके मानदेय से प्रतिमाह 3०० रुपये की प्रस्तावित कटौती नहीं की जाए। इस दौरान पुष्पा, कमला, हेमलता, बबली, उर्मिला, हंसा आदि मौजूद रहीं।

डीजे पर नाचने को लेकर बारात में बवाल, युवक का सिर फोड़ा

रुड़की(आरएनएस)। बूढ़पुर गांव में बारात के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी के बाद गांव के ही दो पक्षों में गाली-गलौज और मारपीट शुरू हो गई।

आरोप है कि चार युवकों ने एक युवक के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल के सिर में चिकित्सकों को 15 टांके लगाने पड़े। ग्राम बूढ़पुर निवासी हिमांशु ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार को गांव में बारात आई हुई थी। बारात में बज रहे डीजे पर गांव के कुछ युवक नाच-गाना कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों के युवकों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद गाली-गलौज और मारपीट में बदल गया।

मासूम के झुलसने के बाद जागा प्रशासन, धनपुरा में शिफ्ट हुई हाईटेंशन लाइन

रुड़की(आरएनएस)। पथरी क्षेत्र के धनपुरा गांव में कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत के प्रस्ताव पर हाईटेंशन लाइन शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। लेकिन, प्रशासन एक बच्ची के झुलसने के बाद नींद से जागा है। लाइन शिफ्टिंग से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है।

समाजसेवी मौ. सलीम और ग्रामीणों के प्रयास से मंगलवार को धनपुरा आबादी के बीच से गुजर रही हाईटेंशन की लाइन शिफ्ट कराई गई। रविवार को लाइन की चपेट में आकर आठ साल की मासूम बच्ची झुलस गई थी। घटना के बाद से मौ. सलीम, उपप्रधान सलीम अहमद और क्षेत्र पंचायत सदस्य मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद ऊर्जा निगम नींद से जागा और लाइन को शिफ्ट करने का कार्य शुरू किया गया। विधायक अनुपमा रावत ने बताया कि धनपुरा आबादी के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन की लाइन को अन्य स्थान पर शिफ्ट कराया गया है।

जीआईएस आधारित कार्यशाला में भूगोल प्रवक्ताओं ने तैयार की अधिगम सामग्री

अल्मोड़ा(आरएनएस)। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) अल्मोड़ा में वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2०26-27 के अंतर्गत जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत भूगोल प्रवक्ताओं के लिए पांच दिवसीय भूस्थानिक तकनीकी (जीआईएस, जीपीएस एवं सुदूर संवेदन) आधारित अधिगम निर्माण कार्यशाला आयोजित की जा रही है।

23 नवंबर से शुरू हुई कार्यशाला के दूसरे दिन प्रतिभागियों ने सुदूर संवेदन एवं मानचित्र निर्माण से संबंधित अधिगम सामग्री तैयार की। कार्यशाला समन्वयक रमेश सिंह रावत ने प्रतिभागियों को कक्षा 11 के भूगोल विषय के प्रयोगात्मक कार्य के अध्याय-4 'सुदूर संवेदन का परिचय' से संबंधित कठिन एवं जटिल पाठ्यक्रम को सरल, रोचक और स्थानीय उदाहरणों के माध्यम से समझाने के लिए अधिगम सामग्री तैयार करने का निर्देशन दिया। उन्होंने मानचित्र निर्माण को आधार बनाकर विषयवस्तु को विद्यार्थियों के लिए अधिक सहज बनाने पर जोर दिया। इसके बाद प्रतिभागियों ने समूहवार सुदूर संवेदन का परिचय, इसकी अवस्थाएं, संवेदक, उपग्रहों की विभेदन क्षमता, संवेदन विभेदन, प्रतिबिंब निर्वचन के तत्व, जीपीएस और मानचित्र निर्माण जैसे विषयों पर चर्चा-परिचर्चा की। इसके आधार पर विभिन्न अधिगम सामग्रियां तैयार कर उनका प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्यशाला समन्वयक रमेश सिंह रावत ने बताया कि कार्यशाला के बाद तैयार की गई सामग्री के आधार पर हस्तपुस्तिका का प्रकाशन किया जाएगा। यह हस्तपुस्तिका भूगोल विषय के शिक्षकों के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगी। कार्यशाला का संचालन रमेश सिंह रावत ने किया, जबकि संस्थान के शैक्षिक तकनीकी विभागाध्यक्ष प्रकाश चंद्र आर्या ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया। कार्यशाला में घनश्याम पांडे, डॉ. अनिल कुमार भारती, पंकज कुमार, मीता वर्मा, यशोदा रमा मेहता, रैना अधिकारी, इंद्र सिंह बिष्ट एवं कामिल हुसैन सहित भूगोल प्रवक्ता उपस्थित रहे।

शरीर को डिटॉक्स और रीढ़ को लचीला बनाता है अर्ध मत्स्येन्द्रासन, जानें लाभ

आधुनिक जीवनशैली और घंटों एक ही जगह बैठकर काम करने की आदत हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। योग के कई आसनों में से अर्ध मत्स्येंद्रासन एक ऐसा आसन है, जो हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है।

यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, पेट के अंगों को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन, हठयोग का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण आसन है, जिसे महान योगी और हठयोग के प्रवर्तकों में से एक, महर्षि मत्स्येंद्रनाथ के नाम पर रखा गया। संस्कृत में अर्ध का अर्थ आधा, मत्स्य का अर्थ मछली और इंद्र का अर्थ राजा होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, इस आसन के नियमित अभ्यास से शरीर की सुप्त ऊर्जा जागृत होती है और रीढ़ का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। यह आसन केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक विधि है।

यह एक प्रमुख ट्विस्टिंग (मोड़ने वाला) योगासन है, जो न केवल शरीर की जकड़न को दूर करता है बल्कि आंतरिक अंगों की मालिश कर शरीर को डिटॉक्स (विषमुक्त) करने में भी मदद करता है। आइए, इस प्राचीन और लाभकारी आसन के महत्व, सही तकनीक और स्वास्थ्य लाभों को विस्तार से समझें।

हठयोग प्रदीपिका में मूल रूप से मत्स्येंद्रासन (पूर्ण मत्स्येंद्रासन) का वर्णन मिलता है। आधुनिक योग अभ्यास में इसी आसन को सरल और सुलभ बनाने के लिए इसके आधे रूप यानी अर्ध मत्स्येंद्रासन का विकास किया गया। इस आसन का नाम नाथ संप्रदाय के महान योगी मत्स्येंद्रनाथ के नाम पर रखा गया है।

अर्ध मत्स्येंद्रासन करने का तरीका भी ज्यादा कठिन नहीं होता और नियमित अभ्यास करने पर इसके परिणाम साफ नजर आने लगते हैं। इस आसन को करने के दौरान शरीर को आधा मोड़ते हैं, जिससे शरीर में खून का संचार बेहतर हो जाता है और ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ता है। यही वजह है कि इसे सबसे बेहतरीन आसनों में से एक माना जाता है।

इसके अलावा, यह आसन मधुमेह के मरीजों के लिए भी मददगार माना जाता है। पेट के हिस्से में खिंचाव होने से अग्न्याशय (पैंक्रियास) की कार्यक्षमता बेहतर होती है, जिससे इंसुलिन का स्राव संतुलित होता है। हालांकि, मधुमेह से जुड़े किसी भी अभ्यास को शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है।

जीभ की सफाई को आसान बनाने के लिए अपनाएं ये आदतें

जीभ की सफाई का ध्यान रखना मुंह की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर लोग ब्रश करते समय जीभ को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे कई समस्याएं हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी आदतें बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी जीभ को साफ और स्वस्थ रख सकते हैं। ये आदतें न केवल आपकी मुंह की सफाई को बेहतर बनाएंगी, बल्कि आपके मुंह की बदबू को भी कम करेंगी।

नियमित रूप से जीभ साफ करें : रोजाना ब्रश करने के बाद अपनी जीभ को साफ करना बहुत जरूरी है। ब्रश करते समय हल्के हाथों से जीभ पर भी ब्रश चलाएं। इससे आपकी जीभ पर जमा हुआ बैक्टीरिया और खाना हट जाएगा।

अगर आप हर बार ब्रश करते समय इसे नहीं कर पाते तो दिन में कम से कम एक बार जरूर अपनी जीभ को साफ करें। इससे आपके मुंह की बदबू कम होगी और आपकी सेहत बेहतर रहेगी।

जीभ की सफाई के लिए सही उपकरण का उपयोग करें : जीभ साफ करने के लिए सही उपकरण का चयन करना अहम है। बाजार में कई प्रकार के जीभ साफ करने वाले उपकरण मिलते हैं, लेकिन आपको वह चुनना चाहिए जो आपके लिए सबसे आरामदायक हो।

प्लास्टिक या स्टील के उपकरण अच्छे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वे नरम हों ताकि जीभ पर किसी प्रकार की चोट न लगे।

इसके अलावा नियमित रूप से अपने उपकरण को भी साफ करें ताकि उसमें बैक्टीरिया न पनप सकें।

हल्के हाथों से जीभ पर ब्रश करें : जब आप अपनी जीभ को साफ करें तो हल्के हाथों से ही ब्रश करें। ज्यादा दबाव डालने से आपकी जीभ घायल हो सकती है और इससे दर्द भी हो सकता है। हल्के हाथों से ब्रश करने पर बैक्टीरिया और गंदगी आसानी से हट जाती है बिना किसी चोट के। आप चाहें तो जीभ साफ करने वाले उपकरण का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसे भी हल्के हाथों से ही इस्तेमाल करें ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो।

मुंह धोना न भूलें : ब्रश करने के बाद अपने मुंह को अच्छी तरह धोना न भूलें। गुनगुने पानी या किसी अच्छे मुंह धोने वाले तरल से अपने मुंह को धोएं।

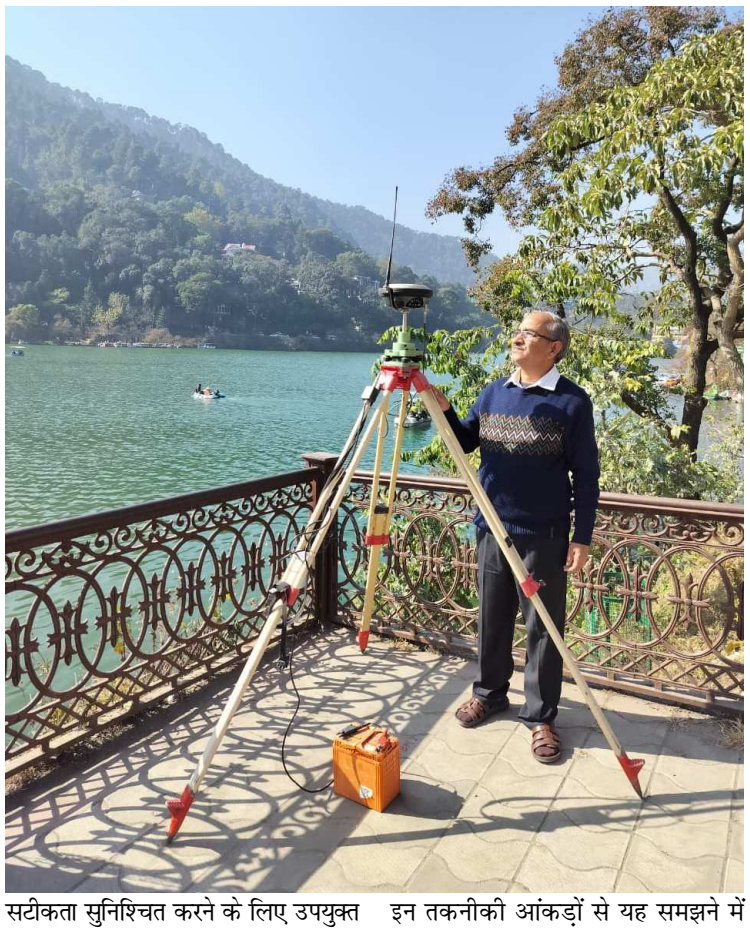
ताकि सभी गंदगी और बैक्टीरिया हट जाएं। इससे आपका मुंह ताजा महसूस होगा और बदबू भी दूर होगी। इसके अलावा यह आपकी मुंह की सफाई को भी बेहतर बनाएगा। ध्यान रखें कि मुंह धोने के बाद पानी न निगलें और कुछ समय तक खाने-पीने से बचें।

दांतों की जांच कराते रहें : भले ही आप घर पर अच्छी तरह से सफाई क्यों न करें, समय-समय पर दांतों की जांच कराना जरूरी है। डॉक्टर आपकी मुंह की सेहत का पता लगा सकते हैं और अगर कोई समस्या हो तो उसका सही इलाज बता सकते हैं।

भीमताल झील के पुनर्जीवन की दिशा में एसएआरआरए की पहल, चार दिवसीय बैथिमेट्रिक सर्वेक्षण संपन्न

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की प्रमुख प्राकृतिक झीलों में शामिल नैनीताल जनपद की भीमताल झील के संरक्षण एवं पुनर्जीवन की दिशा में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी, मुख्यालय देहरादून द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में 20 से 23 नवंबर 2026 तक भीमताल झील का चार दिवसीय विस्तृत बैथिमेट्रिक सर्वेक्षण कराया गया। इस वैज्ञानिक सर्वेक्षण का उद्देश्य झील की वर्तमान गहराई, जल भंडारण क्षमता, झील के तल पर जमा गाद एवं तलछट की स्थिति का सटीक आकलन करना तथा भविष्य में झील के पुनर्जीवन एवं ड्रेजिंग (गाद निकासी) की संभावनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करना है। यह सर्वेक्षण रुड़की स्थित सर्वेक्षण एजेंसी मैसर्स जियोसाइंस कंसल्टेंसी सर्विसेज के माध्यम से आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों की सहायता से संपन्न कराया गया। सर्वेक्षण कार्य के दौरान मोटर बोट पर स्थापित इकोसाउंडर उपकरण के माध्यम से झील के विभिन्न हिस्सों की गहराई का मापन किया गया। वहीं, झील की परिधि पर उपकरण स्थापित कर सर्वेक्षण बिंदुओं की सटीक भौगोलिक स्थिति एवं निर्देशांक दर्ज किए गए। इस तकनीक के माध्यम से झील की गहराई एवं तल की संरचना से संबंधित आंकड़ों का अधिक सटीक और वैज्ञानिक संकलन किया गया। सर्वेक्षण के लिए ड्यूल फ्रीक्वेंसी सिंगल बीम इकोसाउंडर तथा मल्टी-कॉन्स्टेलेशन सिस्टम का उपयोग किया गया। उपकरणों में करेक्शन की व्यवस्था के साथ ट्रांसड्यूसर की माउंटिंग डेप्थ, ऑफसेट तथा जलस्तर का मापन एवं आवश्यक डेप्थ करेक्शन भी तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा रहा। सर्वेक्षण के दौरान लगभग 10 मीटर के अंतराल पर सर्वे ट्रांसेक्ट निर्धारित किए गए। साथ ही सर्वेक्षण की



सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त क्रॉस-चेक लाइन एवं झील की बाउंड्री का भी सर्वेक्षण किया गया।

इस सर्वेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भीमताल झील की वर्तमान स्थिति का वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधार तैयार करना है। इसके अंतर्गत झील की बैथिमेट्रिक कंटूर एवं डेप्थ प्लान, क्रॉस-सेक्शन प्रोफाइल, डिजिटल बेड सरफेस तथा साउंडिंग डेटा तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त झील के तल पर जमा तलछट की मोटाई एवं संभावित ड्रेजिंग की मात्रा का आकलन किया जाएगा। सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर 3क डिजिटल टेरेन मॉडल, 10 मीटर क्रॉस-सेक्शन, झील की कुल जल भंडारण क्षमता, सिल्ट कैपेसिटी तथा एरिया-कैपेसिटी कर्व तैयार किए जाएंगे। इन तकनीकी आंकड़ों से यह समझने में मदद मिलेगी कि वर्तमान में झील की जल संग्रहण क्षमता कितनी है, झील के किन हिस्सों में अधिक तलछट जमा है तथा वैज्ञानिक तरीके से गाद निकासी की कितनी संभावनाएं मौजूद हैं। इस अध्ययन से भविष्य में भीमताल झील के संरक्षण, जल संग्रहण क्षमता के बेहतर प्रबंधन तथा पुनर्जीवन से संबंधित कार्यों की योजना तैयार करने में वैज्ञानिक आधार उपलब्ध होगा।

भीमताल झील का यह अध्ययन उत्तराखंड की महत्वपूर्ण प्राकृतिक जल संपदाओं के दीर्घकालिक संरक्षण एवं सतत प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जिसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ स्थानीय लोगों, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को मिलेगा।

शब्द सामर्थ्य-78

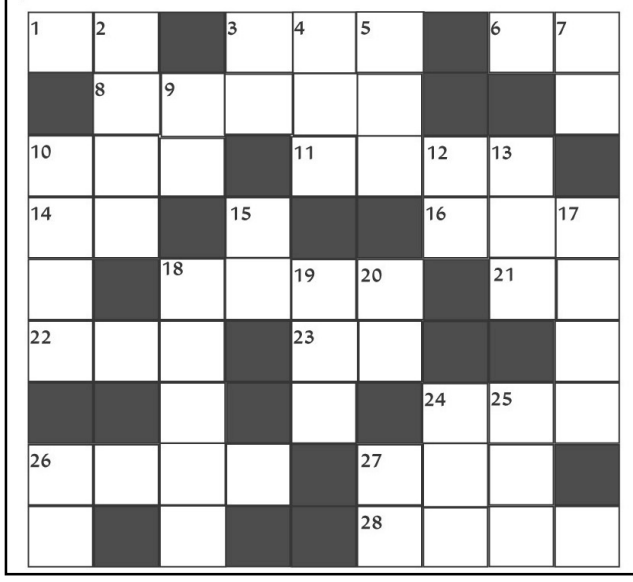
(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. याद, स्मरण 3. अग्नि, आग, पवित्र करने वाला 6. गौ जाति का नर 8. निशाचर, रात में विचरण करने वाला 10. मुस्कुराहट, तबस्सुम 11. खारा, नमक के स्वाद जैसा 14. मुख्यभाग, निचोड़ 16. पिंडली व एड़ी के बीच की दोनों ओर उभरी हड्डी, गुल्फ 18. अद्भूत, विचित्र 21. सम्राट, बादशाह, नरेश 22. कृति, निर्माण करना, बनाना 23. बड़ी थाली 24. समूह, दल 26. एहसानमंद, कृतज्ञ 27. ध्वनि, सदा 28. श्रीकृष्ण के बड़े भाई, हलधर।

ऊपर से नीचे

2. अपमान, अनादर, अवज्ञा 3. जल, नीर, अम्बु 4. वाणी, वादा, कथन 4. कर्म शब्द का अपभ्रंश, भाग्य 7. लकड़ी का घूमने वाला एक गोल खिलौना, बिजली का बल्ब 9. लोग, प्रजा 10. यात्री, राही, पथिक 12. कीड़ा 13. चोचला, अदा 15. दंड 17. अवैध, अनुचित 18. जो आधिकारिक न हो, जो अधिकार प्राप्त न हो 19. जैसा होना चाहिए ठीक वैसा, सत्यपरक, वाजिब 20. ताकत, शक्ति 24. प्रश्न, समस्या 25. घटना, घटना का वर्णन 26. एक प्रसिद्ध पक्षी जो रात में विचरण करता है, लक्ष्मीजी की सवारी 27. पानी, चमक।



शब्द सामर्थ्य क्रमांक 77 का हल

टे	ढ़ा	मे	ढ़ा	■	म	हा	र	त
क	■	ह	■	■	■	■	ज	न
■	जा	न	की	■	क	म	नी	य
■	■	त	म	क	ना	■	■	■
म	■	■	त	ह	त	■	दा	ब
सी	मा	■	■	ला	■	स	न	द
हा	थ	म	ल	ना	■	वा	■	च
■	■	द	■	■	घा	ल	मे	ल
■	ब	द	ह	वा	स	■	■	न

लखवाड़ परियोजना के श्रमिकों को हिरासत में लेने पर उक्रांद ने जताया विरोध

विकासनगर(आरएनएस)। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना में पिछले दस दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे श्रमिकों को पुलिस हिरासत में लिए जाने पर उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने कड़ा विरोध जताया है। दल ने प्रशासन और एलएंडटी कंपनी प्रबंधन की कार्रवाई को श्रमिकों की आवाज दबाने वाला कदम बताते हुए कहा कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे मजदूरों के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। उक्रांद की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जिन श्रमिकों के श्रम और मेहनत से लखवाड़ परियोजना का निर्माण हो रहा है, आज उन्हीं की समस्याओं और मांगों को अनसुना किया जा रहा है।श्रमिक पिछले दस दिनों से यूनियन को मान्यता देने और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने सहित अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसके बावजूद कंपनी प्रबंधन की ओर से उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्रांद के कार्यकारी शहर अध्यक्ष अरविंद तोमर ने श्रम विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि श्रमिकों के अधिकारों और सुविधाओं से जुड़े मामलों में विभाग की चुप्पी चिंताजनक है। मांगों पर बातचीत कर समाधान निकालने के बजाय पुलिस कार्रवाई से श्रमिकों में असंतोष बढ़ेगा। उक्रांद ने कहा कि उत्तराखंड में बाहरी कंपनियों के माध्यम से स्थानीय श्रमिकों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उक्रांद ने शासन-प्रशासन से हिरासत में लिए गए श्रमिकों के मामले में उचित कार्रवाई करने, कंपनी प्रबंधन के अड़ियल रवैये पर रोक लगाने और श्रमिकों की मांगों पर वार्ता कर समाधान निकालने की मांग की।

जनपद में पुलिस ने शुरू किया सघन चेकिंग अभियान

पौड़ी(आरएनएस)। पुलिस विभाग की ओर से जिले में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था मजबूत के लिए सघन चेकिंग और सत्यापन अभियान शुरू कर दिया गया है। एसएसपी सर्वेश पंवार के निर्देशों पर सभी थाना क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। बताया कि अभियान के तहत प्रमुख मार्गों, जनपद के प्रवेश व निकास मार्गों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों व संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष चेकिंग की जा रही है। बाहरी व्यक्तियों, किरायेदारों और बिना सत्यापन रह रहे लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। अभियान के तहत डबल हेलमेट के लिए जागरूकता और शराब पीकर वाहन चलाने, तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।

फोन पर झांसा देकर बैंक खाते से उड़ाए 29 हजार रुपये

रुड़की(आरएनएस)। साइबर ठगों ने फोन पर एक व्यक्ति को अपनी बातों में उलझाकर उसके बैंक खाते से 29 हजार रुपये निकाल लिए। खाते से रकम निकलने का मैसेज मिलने पर पीड़ित को ठगी का पता चला। पीड़ित ने सिविल लाइंस कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के खंजरपुर निवासी आदेश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दो दिन पहले उसके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति की कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को इस तरह पेश किया कि वह उसकी बातों में आ गया। आरोप है कि ठग ने उसे झांसे में लेकर एटीएम का पिन कोड और बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल कर ली।

खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए किया जागरूक

अल्मोड़ा(आरएनएस)। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा की ओर से निदेशक डॉ. लक्ष्मीकांत के निर्देशन में चलाए जा रहे 'खेत बचाओ अभियान' के तहत विकासखंड हवालबाग के ग्राम चाण में किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को अभियान के उद्देश्यों से अवगत कराने के साथ जैविक एवं प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में किसानों को खेती में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक एवं असंतुलित उपयोग को कम करने, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता बनाए रखने तथा पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने के महत्व की जानकारी दी गई। किसानों को जैविक खाद, कम्पोस्ट, हरी खाद तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया। किसानों को बताया गया कि रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता से मिट्टी की गुणवत्ता और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता बनाए रखने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जैविक एवं प्राकृतिक खेती को अपनाना आवश्यक है। इस दौरान पर्वतीय कृषि को अधिक टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और लाभकारी बनाने में किसानों की सक्रिय भागीदारी पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. पंकज मिश्रा एवं डॉ. डी.सी. जोशी ने किया। उन्होंने किसानों से 'खेत बचाओ अभियान' से जुड़कर मृदा स्वास्थ्य के संरक्षण, रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग तथा जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम चाण के किसानों में टिकाऊ कृषि, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया।

मुख्यमंत्री धामी को सिख समुदाय ने दी 'शेर-ए-उत्तराखण्ड' की उपाधि'

◆गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर गूंजा भाईचारे का संदेश



हमारे संवाददाता

देहरादून। गुरु नानक देव जी महाराज के प्रथम प्रकाश पर्व (गुरुपर्व) के उपलक्ष्य में 24 नवंबर को गुरुद्वारा गोविंदनगर, रेसकोर्स, देहरादून में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बलजीत सोनी एवं सिख समुदाय के तत्वावधान में भव्य एवं श्रद्धापूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग कर गुरु महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की तथा उनके बताए प्रेम, सेवा, समानता और आपसी भाईचारे के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर मत्था टेका तथा गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए समाज में आपसी सद्भाव, एकता, सौहार्द एवं भाईचारे की भावना को मजबूत बनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर सिख समुदाय के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को 'शेर-ए-उत्तराखण्ड' की उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से जन-जागरूकता की विशेष पहल भी की गई। विभागीय प्रतिनिधियों ने गुरुद्वारा परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न रोजगारपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही योजनाओं से संबंधित ब्रोशर एवं प्रचार-प्रसार सामग्री वितरित कर पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।

इस पहल का उद्देश्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उस संकल्पना को साकार करना है, जिसके तहत समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के माध्यम से जनसामान्य तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का यह प्रयास शासन की जनकल्याणकारी नीतियों को आमजन से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव जी महाराज के आदर्शों का स्मरण करते हुए कहा कि उनके जीवन दर्शन में मानवता की सेवा, समानता, प्रेम, सद्भाव और निःस्वार्थ सेवा का संदेश निहित है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी समाज को भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट रहने तथा मानव कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा देती हैं।

कार्यक्रम में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के सचिव बरकत अली, संजय रावत, श्रीमती दीपा, श्रीमती शमा, प्रतीक, कमल सिंह एवं प्रमोद सहित विभागीय प्रतिनिधि, सिख समुदाय के गणमान्य व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

आधार केंद्र से लेकर स्वास्थ्य तक सभी सुविधाएं बदहाल

उत्तरकाशी(आरएनएस)। चिन्यालीसौड़ और आसपास के इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। चिन्यालीसौड़ में आधार सेवा केंद्र का नियमित संचालन नहीं होने से लोगों को आधार कार्ड बनवाने और संशोधन के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। हातड़ क्षेत्र के कई गांव मोबाइल नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं।

संचार सुविधा नहीं होने से ग्रामीणों को आपातकालीन स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजमर्रा के कामकाज में दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। लोगों ने समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन बडोनी ने जनप्रतिनिधियों को भेजे पत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी चिंता जाहिर की।

उन्होंने बताया कि सीएचसी चिन्यालीसौड़ में विशेषज्ञ चिकित्सकों और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को बेहतर उपचार के लिए दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। वहीं बनचौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड की जांच की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों को छोटी-छोटी जांचों के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। इसके अलावा चिन्यालीसौड़ ऑलवेदर रोड क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। विधानसभा क्षेत्र की कई लोनिवि और पीएमजीएसवाई की सड़कें भी गड्ढों और क्षतिग्रस्त हिस्सों के कारण बदहाल हैं जिससे आवागमन जोखिमभरा बना हुआ है।

उन्होंने आधार केंद्र का नियमित संचालन, हातड़ में मोबाइल नेटवर्क, पेयजल व्यवस्था, चिन्यालीसौड़ सीएचसी का उच्चीकरण, बनचौरा में ब्लड जांच सुविधा और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की है।

पार्किंग से लेकर सुरक्षा और सफाई व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश

कोटद्वार(आरएनएस)। सिद्धबली बाबा अनुष्ठान महोत्सव की तैयारियों को लेकर मंगलवार को सिद्धबली मंदिर परिसर में एसडीएम संदीप कुमार ने अधिकारियों और मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

उन्होंने चार दिसंबर से शुरू होने वाले तीन दिवसीय महोत्सव को लेकर सभी विभागों को व्यवस्थाएं समय से पूरा करने के निर्देश दिए।कोतवाल प्रदीप नेगी ने बताया कि महोत्सव के दौरान वाहनों की पार्किंग के लिए डिग्री कॉलेज मार्ग, जल संस्थान कार्यालय, पुलिंडा मार्ग, ग्रास्टनगंज स्थित दशहरा मैदान और कार्बेट होटल के पास स्थान चिह्नित किए गए हैं। वाहन मॉडल मांटेसरी से गाड़ीघाट होते हुए ग्रास्टनगंज दशहरा मैदान तक पहुंच सकेंगे। एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग को महोत्सव के दौरान आधुनिक सुविधाओं से लैस एंबुलेंस तैनात करने के निर्देश दिए। वहीं, मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने नगर निगम से चार मोबाइल टॉयलेट उपलब्ध कराने और मेले के दौरान सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने की मांग की।

बताया गया कि शोभायात्रा में नगर निगम की ओर से स्वच्छता संबंधी झांकी निकाली जाएगी। साथ ही पर्यावरण मित्र सड़क पर गिरने वाले कचरे की तत्काल सफाई करेंगे। वन्यजीवों के खतरे को देखते हुए वन विभाग को मंदिर के आसपास गश्त बढ़ाने, ऊर्जा निगम को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और सड़क किनारे पड़े बिजली के पोल हटाने के निर्देश दिए गए। जल संस्थान को शोभायात्रा और मेले के दौरान पानी के टैंकरों की व्यवस्था करने को कहा गया।

बैठक में महंत दिलीप रावत, मंदिर समिति अध्यक्ष डॉ. जेपी ध्यानी, सेवकराम मानूजा, विवेक अग्रवाल, ऋषभ भंडारी, दीपू पोखरियाल, जितेंद्र कैंथोला, अनुष्ठान महोत्सव के सचिव राजेश रावत, ऊर्जा निगम के एसडीओ कमल सिंह, मुख्य सफाई निरीक्षक सुनील कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

डॉ. रमा को मिला 'मदर टेरेसा ग्लोबल समर्पण समाज गौरव सम्मान

◆सामाजिक सेवा के लिए अंतरराष्ट्रीय समारोह में किया गया सम्मानित



हमारे संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है कि देहरादून की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था हर्षल फाउंडेशन की ट्रस्टी एवं सचिव डॉ. रमा गोयल को सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। उन्हें जयपुर में आयोजित 11वें ग्लोबल समर्पण समाज गौरव-2026 समारोह में प्रतिष्ठित 'मदर टेरेसा ग्लोबल समर्पण समाज गौरव 2026' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

समर्पण संस्था द्वारा 22 नवंबर 2026 को जयपुर स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के न्यू ऑडिटोरियम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार समारोह 2026 में डॉ. रमा गोयल को यह सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें मानवता की सेवा, निस्वार्थ सामाजिक योगदान और समाज के उत्थान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया। डॉ. रमा गोयल हर्षल फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। उनका यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों की पहचान है, बल्कि देहरादून और उत्तराखंड में सामाजिक सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाता है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जयपुर के अध्यक्ष देवेंद्र मोहन माथुर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज्यसभा सांसद राम कुमार वर्मा ने की। इस अवसर पर समर्पण संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आर्किटेक्ट डॉ. दौलत राम माल्या सहित अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे।

सू- दोकू क्र. 78

		3					7	
9				6		3		8
	7		9		5		6	
						1		9
3		8		7			5	
	1		3		9			7
		2		8		7		
	8				2		4	3
			1					

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.77 का हल

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6

भाजपा सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना होगा, दस हजार रुपए का प्रलोभन देकर वोट खरीदने नहीं देंगे: जैन

नगर संवाददाता

देहरादून। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार द्वारा बैणी-भुली योजना के अंतर्गत प्रदेश की लगभग 5.23 लाख महिलाओं को रू. 10,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा पर सवाल उठाते हुए इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश बताया है।

आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष शरद जैन का कहना है कि भाजपा सरकार अपने कार्यकाल में युवाओं को पर्याप्त रोजगार देने, बेरोजगारी की समस्या दूर करने और अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है। अब जब सरकार के पास जनता को बताने के लिए अपनी उपलब्धि यां नहीं हैं, तो चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खातों में धनराशि भेजकर उनके वोट प्रभावित करने की रणनीति अपनाई जा रही है।

पार्टी ने सवाल उठाया कि यदि भाजपा सरकार वास्तव में महिला सशक्तिकरण के प्रति गंभीर होती, तो उसे चुनाव से कुछ महीने पहले इस प्रकार की घोषणाएं करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थायी रोजगार, स्वरोजगार के अवसर, सुरक्षित कार्यस्थल, शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देने की ठोस व्यवस्था क्यों नहीं की गई?

आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति भी गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में कूड़े के ढेर में एक अज्ञात महिला का शव मिलने की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। हल्द्वानी में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। वहीं पौड़ी गढ़वाल के कोटड़ीधांग गांव में चारा लेने गई महिला की गुलदार के हमले में मौत हो गई। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष प्रदेश में गुलदार के हमलों में कम से कम 18 और बाघों के हमलों में पांच लोगों की जान जा चुकी है। ये घटनाएं महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय करने की आवश्यकता को दर्शाती हैं।

आम आदमी पार्टी ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले 5 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणा और इसे चुनाव से पहले गेम चेंजर बताना सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि इस योजना का उद्देश्य वास्तविक आर्थिक सशक्तिकरण है, तो सरकार को इसकी पारदर्शी पात्रता, बजट, लाभार्थियों के चयन और दीर्घकालिक रोजगार परिणामों का विवरण सार्वजनिक करना चाहिए।

पार्टी निर्वाचन आयोग से भी मांग करती है कि इस घोषणा और चुनाव से पहले इसके क्रियान्वयन की निष्पक्ष जांच की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं सरकारी धन और योजनाओं का इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने या आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए तो नहीं किया जा रहा है।

आम आदमी पार्टी स्पष्ट करना चाहती है कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण किसी चुनावी प्रलोभन का विषय नहीं है। उत्तराखंड की माताओं और बहनों ने राज्य निर्माण से लेकर प्रदेश के विकास तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका वोट किसी आर्थिक सहायता की कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता। भाजपा सरकार को समझना होगा कि लोकतंत्र में जनता को आर्थिक घोषणाओं से प्रभावित करने के बजाय अपने काम का हिसाब देना पड़ता है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को जनता के बीच उठाएगी और बैणी-भुली योजना की आड़ में होने वाली कथित चुनावी राजनीति का पर्दाफाश करेगी।

महिलाओं को रू 10,000 की सहायता से अधिक जरूरी है सम्मान, सुरक्षा, न्याय और स्थायी रोजगार। लोकतंत्र में वोट जनता का अधिकार है, किसी सरकार की खरीद-फरोख्त का साधन नहीं।

निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन

नगर संवाददाता

देहरादून। स्वर्गीय अमर मेहता मेमोरियल चौरिटेबल ट्रस्ट की ओर से निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन मां सुरकंडा मंदिर पथरी बाग चौक देहरा खास धर्मपुर विधानसभा में किया गया ,ट्रस्ट के अध्यक्ष आलोक मेहता ने बताया कि इस ट्रस्ट में लोगों को विभिन्न प्रकार के सहायता उपकरण वितरित किए गए जिसमें व्हीलचेयर स्टिक कान की मशीन कमर की बेल्ट और ब्लड डोनेशन का भी आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने किया और उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो सामाजिक कार्य ट्रस्ट द्वारा किए जाते हैं वह बहुत ही सराहनीय हैं और आगे भी इस प्रकार के आयोजन किए जाएं ताकि आम जनता को इसे लाभ मिल सके और समाज सेवा के कार्य ऐसे ही करते रहना चाहिए। चिकित्सा शिविर के आयोजन के लिए उन्होंने ट्रस्ट के सदस्यों और मेहता परिवार को धन्यवाद दिया और बधाई दी।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से, डॉ जितेंद्र डॉक्टर तन्वी डॉक्टर सव, डॉक्टर दीपांशु डॉक्टर विकास, पूर्व राज्य मंत्री मनीष कुमार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नवीन जोशी देहरादून के प्रभारी विजय गुनसोला, कांग्रेस नेता वैभव वालिया, हरिप्रसाद भट्ट मगू भाई प्रमोद कुमार मुंशी जगदीश धीमान भूरा भाई श्रीमती पिया थापा, एवलिन धजल,अनुभव गुप्ता समीर ऋषभ सैनी असीम रजत लकी ललित बद्री सुरेंद्र रामगढ़ नितिन रावत पारस अयाजउद्दीन सिद्दीकी समेत अन्य कार्यकर्ता वी ट्रस्ट के सदस्य उपस्थित थे।



मुख्यमंत्री ने 36 नवनियुक्त नायब...

◀◀ पृष्ठ 1 का शेष

बनाने के साथ ही नागरिकों को उनके आवेदनों की स्थिति के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने और युवाओं की मेहनत एवं भविष्य की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। पिछले 5 साल में 36 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक नियुक्ति के पीछे किसी युवा की वर्षों की मेहनत और उसके परिवार की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अधिकारियों से अपने पद की गरिमा बनाए रखने, जनता के प्रति संवेदनशील रहने तथा प्रत्येक निर्णय ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ लेने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की पहचान इस बात से बनेगी कि आमजन कितने विश्वास के साथ अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते हैं और उन्हें कितनी सहजता से समाधान मिलता है।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने नवनियुक्त नायब तहसीलदारों को बधाई देते हुए कहा कि यह केवल सरकारी सेवा नहीं, बल्कि जनसेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। राजस्व प्रशासन के माध्यम से आमजन को अधिक से अधिक लाभ कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसी सोच के साथ अधिकारियों को कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन लोगों के प्रति अधिकारियों की विशेष जिम्मेदारी है, जिनकी पहुंच केवल तहसील स्तर तक ही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त अधिकारी जिस ध्येय के साथ सरकारी सेवा में आए हैं, उसे प्राप्त करने में सफल होंगे। इस अवसर पर सचिव राजस्व एस. एन. पाण्डेय, सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद श्रीमती रंजना राजगुरु एवं राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

पहाड़ में एक पूरा गांव 'उजड़ा'...

◀◀ पृष्ठ 1 का शेष

केवल आश्वासन न मिले, बल्कि समयबद्ध आर्थिक सहायता भी मिले। पवाणी की राख से एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आखिर पहाड़ के गांवों को हर आपदा के बाद अपनी किस्मत के भरोसे क्यों छोड़ दिया जाता है? क्या अग्निकांड से बचाव के लिए गांवों में पानी के टैंक, अग्निशमन उपकरण और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या संवेदनशील गांवों की पहचान कर पहले से सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जा सकते? 33 मकानों का जलना केवल संपत्ति का नुकसान नहीं है। यह पहाड़ के ग्रामीण जीवन की असुरक्षा का आईना है। अगर इस घटना के बाद भी व्यवस्था नहीं जागी तो अगली बार किसी दूसरे गांव की बारी हो सकती है। पवाणी को राहत जरूर चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत उस व्यवस्था की है जो अगली बार किसी गांव को इस तरह राख होने से बचा सके।

चुनाव की 'आहट' सड़कों पर 'जनसैलाब'

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

की मांग कर रहे हैं तो उनके सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड में चुनावी मुकाबला अब केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की लड़ाई तक सीमित नहीं रहने वाला। बेरोजगारी, पलायन, महिला सुरक्षा, जमीन, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। सड़कों पर उठने वाली आवाजें यदि गांवों और विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचती हैं तो उनका असर राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है।

फिलहाल प्रदेश में धरने-प्रदर्शनों की बढ़ती संख्या सत्ता के लिए चेतावनी और विपक्ष के लिए अवसर बनती दिखाई दे रही है। लेकिन आंदोलनों की असली ताकत उनकी भीड़ से नहीं, उनके मुद्दों और जनसमर्थन से तय होगी। चुनाव से पहले सड़क पर उतरने वाले हर संगठन और राजनीतिक दल की परीक्षा भी इसी कसौटी पर होगी। आखिरकार सवाल यही है कि उत्तराखंड में आंदोलन चुनाव देखकर तेज हो रहे हैं या चुनाव से पहले जनता का दबा हुआ असंतोष सड़कों पर फूट रहा है? सत्ता के लिए यह सवाल जितना महत्वपूर्ण है, विपक्ष के लिए भी उतना ही कठिन है।

थाली में 'बीमारी' परोस रहा 'बाजार'..

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

भोजन और खाद्य विषाक्तता तत्काल स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकते हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा को केवल विभागीय औपचारिकता बनाकर नहीं छोड़ा जा सकता। विडंबना यह है कि मिलावट पकड़ने के लिए छापेमारी होती है, नमूने लिए जाते हैं, रिपोर्ट आती है और कार्रवाई की खबरें भी बनती हैं। लेकिन आम उपभोक्ता के मन में एक सवाल कायम रहता है कि बाजार में सुरक्षित भोजन की गारंटी आखिर कौन देगा? त्योहारों के समय मिठाई और दूध के नमूने लेने की सक्रियता दिखाई देती है, लेकिन क्या पूरे साल इसी गंभीरता से निगरानी होती है? कितने कारोबारियों के लाइसेंस रद्द हुए? कितनों को सजा मिली? कितने मामलों में दोषियों से जवाबदेही तय हुई?

देश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और खाद्य सुरक्षा कानून मौजूद हैं। खाद्य कारोबारियों के लिए मानक निर्धारित हैं। निरीक्षण और नमूना जांच की व्यवस्था भी है। फिर भी मिलावट की शिकायतें सामने आती हैं तो निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सरकार को बताना होगा कि खाद्य सुरक्षा विभागों में पर्याप्त कर्मचारी हैं या नहीं? प्रयोगशालाओं में जांच की क्षमता कितनी है? नमूनों की रिपोर्ट आने में कितना समय लगता है? दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का परिणाम क्या रहा? केवल नमूने भरने और प्रेस विज्ञप्ति जारी करने से जनता की सेहत सुरक्षित नहीं होगी। जरूरत ऐसी व्यवस्था की है, जिसमें मिलावटखोरों को कारोबार करने से पहले कई बार सोचना पड़े।

कभी कहा जाता था कि जैसा अन्न, वैसा मन। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि सवाल पूछना पड़ रहा है कि जैसा अन्न, वैसी बीमारी तो नहीं? जिस देश में अन्न को देवता माना जाता है, वहां थाली की शुद्धता पर सवाल उठना पूरे समाज और व्यवस्था के लिए शर्मनाक है। आखिर पेट भरने के लिए इंसान खाना खाए या यह सोचकर डरे कि आज की थाली कल अस्पताल का रास्ता न बन जाए?

संरक्षित खेती का प्रशिक्षण लेनें के दल को मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

हमारे संवाददाता

देहरादून। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने कैंप कार्यालय से जनपद देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों के नाबार्ड योजनांतर्गत स्थापित पॉलीहाउस में खेती कर रहे 28 किसानों के दल को संरक्षित खेती का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।



किसानों का यह दल पंतनगर विश्वविद्यालय में पांच दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को संरक्षित खेती की आधुनिक तकनीकों, पॉलीहाउस प्रबंधन, उन्नत कृषि पद्धतियों, फसल उत्पादन, कीट एवं रोग प्रबंधन तथा वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की बारीकियों की जानकारी दी जाएगी।

इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध करा रही है। उन्होंने

◆प्रशिक्षण में किसानों को खेती की बारीकियों से कराया जाएगा अवगत

कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में संरक्षित खेती किसानों के लिए स्वरोजगार और आय बढ़ाने का एक बेहतर माध्यम है। पॉलीहाउस के माध्यम से किसान कम भूमि में भी बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना और उन्हें वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद किसान अपने क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करेंगे और अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर जिला उद्यान अधिकारी डॉ डी.के.तिवारी भी उपस्थित रहे।

नन्ही परी के लिए 29 नवंबर को पिथौरागढ़ में होगी महापंचायत

नगर संवाददाता

पिथौरागढ। नन्ही परी को न्याय दिए जाने के आंदोलन को उत्तराखंड में 29 नवंबर को पुन: जन संगठनों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों की महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत में आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। महापंचायत में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की जाएगी।

नन्ही परी के ताऊ ने बताया कि 20 नवंबर को हुए श्रद्धांजलि सभा में पिथौरागढ़ के साथ-साथ हल्द्वानी और देहरादून में जनता के द्वारा दिए गए सहयोग से न्याय की आवाज को उठाने में उनके परिवार को मदद मिली है।

उन्होंने बताया कि आंदोलन को आगे अंजाम तक ले जाने के लिए 29 नवंबर को नन्ही परी के पिता महेश चंद के आवास पंडा पिथौरागढ़ में महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत में जनपद के

◆पीड़ित परिवार अब जाएगी जनता की अदालत में, रिव्यू पिटीशन दर्ज हुआ लेकिन नहीं हुई सुनवाई

समस्त जन संगठनों, राजनीतिक दलों के अलावा जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। महापंचायत में आपसी विचार विमर्श के बाद आंदोलन को चरणबद्ध चलाने की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष हुए आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दर्ज किया था। आज तक रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के लिए एक तारीख तक नहीं लग पाई है। उन्होंने कहा कि नन्ही परी के कातिल खुलेआम घूम रहे है। पीड़ित परिवार को न्याय दिए जाने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने अब जनता की अदालत में जाने का फैसला ले लिया है। उन्होंने आशा जताई कि उत्तराखंड की जनता इस पीडित परिवार को अंतिम न्याय दिलवाने के लिए आगे आकर चरणबद्ध आंदोलन में सहयोग देगी। उन्होंने सीमांत जिले के समस्त जन संगठनों, राजनीतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों को इस महापंचायत में शामिल होने की अपील की।

29 नवंबर को सागरताल में सजेगा 52वां खलंगा मेला

हमारे संवाददाता

देहरादून। ऐतिहासिक खलंगा युद्ध के वीर सेनानायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों के अदम्य साहस एवं शौर्य को नमन करने के लिए 29 नवंबर को सागरताल, नालापानी में 52वें खलंगा मेले का आयोजन किया जाएगा। बलभद्र खलंगा विकास समिति की ओर से आयोजित होने वाले इस मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ गोरखाली लोक संस्कृति की विशेष झलक देखने को मिलेगी।

स्थानीय क्लब देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता में समिति के अध्यक्ष कर्नल विक्रम सिंह थापा ने बताया कि समिति पिछले 51 वर्षों से इस मेले का आयोजन कर रही है। वर्ष 1814-16 में खलंगा युद्ध के दौरान सेनानायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों एवं वीरांगनाओं ने शक्तिशाली ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया था। उनकी वीरता और अदम्य पराक्रम को याद करते हुए प्रतिवर्ष श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मेले का आयोजन किया जाता



है। समिति के सचिव संजय थापा ने बताया कि दो दिवसीय आयोजन की शुरुआत 28 नवंबर को सुबह 6:45 बजे सहस्रधारा रोड स्थित खलंगा युद्ध स्मारक पर सेनानायक बलभद्र थापा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ होगी। इसके बाद सुबह सात बजे स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश देने के लिए साइकिल रैली निकाली जाएगी। यह रैली खलंगा युद्ध स्मारक से शुरू होकर सागरताल स्थित खलंगा युद्ध कीर्ति स्तंभ पर संपन्न होगी। 29 नवंबर को सुबह 10:30 बजे सागरताल में मुख्य मेले का शुभारंभ होगा। इसमें खलंगा युद्ध के इतिहास का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। साथ ही गोरखाली, गढ़वाली और कुमाऊंनी लोकगीतों एवं लोकनृत्यों की रंगारंग प्रस्तुतियां होंगी। गोरखाली व्यंजनों, पारंपरिक परिधानों और आभूषणों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। मेले में लकी ड्रॉ, प्रसिद्ध खुकरी नृत्य और गोरखाली संस्कृति के पारंपरिक नौमती बाजा की प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण रहेंगी।

पत्रकार वार्ता में समिति की उपाध्यक्ष विनय गुरुंग, सचिव संजय थापा, सहसचिव केबी कार्की, कोषाध्यक्ष महेश भूषाल, डीके बोहरा, एनएस गुरुंग, जितेंद्र खत्री, कर्नल दीवान सिंह खड़का, अशोक वल्लभ शर्मा, रणबीर थापा छेत्री, माया राणा और मणिलाल गिरि सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे।

बेटी को न्याय दिलाने के लिए अंकिता भण्डारी के माता पिता बैठे धरने पर

◆पूर्व सीएम हरीश रावत सहित विभिन्न संगठनों-दलों ने दिया समर्थन



संवाददाता

देहरादून। अंकिता भण्डारी को न्याय दिलाने के लिए अंकिता के माता पिता गाधी पार्क में धरने पर बैठे। इस दौरान कांग्रेस सहित विभिन्न दलों व संगठनों ने वहां पर पहुंच उनका समर्थन किया और वीवीआईपी का नाम सरकार के द्वारा उजागर करने की मांग की।

आज यहां अंकिता भण्डारी के माता पिता गांधी पार्क में पहुंचे और उन्होंने वहां पर धरना दिया। अंकिता भण्डारी के माता पिता के धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पार्षद प्रकाश नेगी, अर्जुन सोनकर, पूर्व विधायक राजकुमार, मजदूर नेता समर भण्डारी सहित विभिन्न संगठनों के लोग वहां पर पहुंचे और उनको अपना समर्थन दिया। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि एक तारफ हमारे देश में अंकिता भण्डारी को न्याय दिलाने के लिए माता पिता संघर्ष कर रहे है दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा और आजादी के लिए सडक पर उतरती सैकडों छात्राएं हैं। महिला सुरक्षा के नाम पर यद्यपी मोदी और योगी-धामी सरकारें बडे-बडे दावे करती हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' जैसे नारे दिये जाते हैं लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग दिखायी देती है। महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन उत्पीडन, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, साईबर अपराध और भेदभाव की घटनाएं बढती जा रही है। जब कोई घटना होती है तो कभी लडकियों को रात में बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है तो कभी उनके पहनावे और व्यवहार पर सवाल उठाए जाते हैं। अपराधियों पर कार्रवाई और सुरक्षित सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के बजाय महिलाओं की आजादी पर ही पहरा लगाने की कोशिश होती है। उन्होंने कहा कि अन्याय के सामने चुप रहना कोई विकल्प नहीं है। जब महिलाएं, छात्राएं मजदूर, नौजवान और समाज के न्यायप्रिय लोग एकजुट होकर अंकिता को न्याय दिलाने की लडाई, दिल्ली की छात्राओं का प्रतिरोध कार्यस्थलों पर यौन उत्पीडन के खिलाफ महिलाओं की आवाज और घरेलू हिंसा के खिलाफ संघर्ष इन सभी को एक दूसरे से जोडें आवश्कता है कि किसी भी महिला के साथ होने वाली हिंसा को केवल उसका व्यक्तिगत मामला न समझें, बल्कि उ से अपनी सामूहिक लडाई बनाएं। इस दौरान प्रगतिशील महिला एकता केन्द्र के द्वारा महिला हिंसा व उससे लडने के लिए महिलाओं को जागरूक करने के लिए पर्चे भी बांटे।

समाज कल्याण अधिकारी पर किया चाकू से हमला!

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। पथरी क्षेत्र में प्रेम विवाह से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत के दौरान हिंसा हो गई। शिवगढ़ गांव में पंचायत के बीच सहायक समाज कल्याण अधिकारी पर चाकू से हमला किए जाने का आरोप है। हमले में उनकी गर्दन और दाएं कंधे पर चोट आई, जिसके बाद उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार शिवगढ़ गांव निवासी कमलेश पौड़ी गढ़वाल के जहरीखाल क्षेत्र में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात हैं। इन दिनों वह अवकाश पर अपने गांव आए हुए थे। इसी दौरान गांव के एक युवक और युवती के प्रेम प्रसंग तथा घर से भागकर शादी करने का मामला सामने आया। बताया गया कि प्रेमी युगल को इस मामले में उच्च न्यायालय से सुरक्षा देने के आदेश भी प्राप्त हैं। प्रेम विवाह के मामले को लेकर युवती पक्ष के लोगों की ओर से गांव में पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में कमलेश भी मौजूद थे। इसी दौरान बातचीत के बीच विवाद बढ़ गया।



आरोप है कि धर्मेंद्र, अमरपाल और वेदपाल राणा ने कमलेश पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से उनकी गर्दन और दाएं कंधे पर चोटें आईं। घटना के बाद पंचायत में मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घायल अधिकारी का मेडिकल परीक्षण कराया और मामले में तीनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पथरी थाना प्रभारी रविंद्र कुमार के अनुसार, आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

25 लाख की चरस सहित तस्कर गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

देहरादून। नशा तस्करी में लिप्त एक व्यक्ति को एसटीएफ व पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसके पास से चार किलो 100 ग्राम चरस बरामद की गयी है। बरामद चरस को आरोपी यूपी के बरेली जिले में सप्लाई करने वाला था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मादक पदार्थों एवं नशीली दवाओं की तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स कुमाऊँ यूनिट द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध लगातार सूचनाएं विकसित कर कार्रवाई की जा रही है। बताया कि इसी क्रम में एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स कुमाऊँ यूनिट एवं थाना लोहाघाट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना लोहाघाट क्षेत्र, जनपद चम्पावत में प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से कुल 4 किलो 100 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी द्वारा बताया गया कि वह उक्त चरस को लोहाघाट क्षेत्र से एकत्रित कर बरेली, उत्तर प्रदेश में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए ले जा रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस.टी. एफ ने बताया कि एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स कुमाऊँ यूनिट द्वारा गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जिसका नाम सुरेश सिंह तिसल्ला पुत्र दान सिंह तिसल्ला, निवासी खतेड़ा मल्ला, थाना पंचेश्वर, जनपद चम्पावत बताया गया है।

दो सड़क हादसों में 3 की मौत, एक गम्भीर रूप से घायल

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में बीती देर रात दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं ने तीन परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। कलियर क्षेत्र में रहमतपुर रोड पर निर्माणाधीन पुलिया से बाइक टकराने पर एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं, रुड़की के बीटीगंज क्षेत्र में दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में दो युवकों की जान चली गई। एक ही रात में तीन युवकों की मौत से इलाके में शोक का माहौल है।

पहली दुर्घटना कलियर थाना क्षेत्र के रहमतपुर रोड पर हुई। जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार दो युवक सड़क से गुजर रहे थे, तभी उनकी बाइक निर्माणाधीन पुलिया से टकरा गई। टक्कर



इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। इस दुर्घटना में 32 वर्षीय अज्जू उर्फ अजय पुत्र ऋषिपाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, बाइक पर सवार 24 वर्षीय आकाश पुत्र मुकेश, निवासी लंढौरा, गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिवार में मातम छा गया।

दूसरी दुर्घटना रुड़की के बीटीगंज क्षेत्र में हुई, जहां दो बाइकों के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर जुटे लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 24 वर्षीय अर्श पुत्र याकूब, निवासी रघुनाथ प्लॉट के पास रुड़की, और 31 वर्षीय मोनू, निवासी दधेड़ू खुर्द, थाना चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। रुड़की में एक ही रात में हुए दो हादसों ने सड़क सुरक्षा और निर्माण कार्यों के दौरान जरूरी सावधानियों को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

आउटसोर्स कर्मचारियों ने किया सचिवालय कूच

संवाददाता

देहरादून। संयुक्त मोर्चा आउटसोर्स कर्मचारी संघ के बैनर तले आउटसोर्स कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया। जिनको पुलिस ने बैरकेडिंग पर रोक दिया। जिसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्य सचिव को ज्ञापन प्रेषित किया गया।

आज यहां आउटसोर्स कर्मचारी परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। जहां से उन्होंने संयुक्त मोर्चा आउटसोर्स कर्मचारी संघ के बैनर तले सचिवालय के लिए कूच किया। जब वह सचिवालय के करीब पहुंचे तभी पुलिस ने बैरकेडिंग लगाकर उनको रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच तीखी नोंक झोंक भी हुई और वह वहीं धरने पर बैठ गये। उनको कहना है कि संघ द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों में



कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है। इजिसके तहत 21 सितम्बर को रैली तथा 6 व 7 अक्टूबर को देहरादून में अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन किया गया था। शासन स्तर पर हुई वार्ता के उपरांत समस्त कर्मचारियों का विभागवार डाटा एकत्रित कर मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडेय को सौंपा गया था। उनके द्वारा दो नवम्बर को बैठक आयोजित किये जाने हेतु मुख्य सचिव को पत्र भी प्रेषित किया गया था। इसके बावजूद आज तक कर्मचारियों के भविष्य को लेकर कोई सकारात्मक बैठक अथवा निर्णय नहीं लिया गया। इसी कारण विवश होकर संघ के समस्त कर्मचारियों को 23 नवम्बर से परेड ग्राउंड में अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन प्रारम्भ करना पडा तथा 24 नवम्बर को मुख्यमंत्री आवास घेराव किया गया था तथा आज सचिवालय कूच करने को बाध्य होना पडा।

उन्होंने कहा कि आज आउटसोर्स कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों उनके हित एवं बेहतर भविष्य को लेकर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो 26 नवम्बर को संयुक्त मोर्चा राज्यपाल निवास घेराव करने को बाध्य होंगे तथा यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्य सचिव को ज्ञापन प्रेषित किया।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।